

दैनिक

रोकथोक लेखनी

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मंत्रालय भवन में किसानों का प्रदर्शन
शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश



मुंबई : मुंबई में मंत्रालय भवन के अंदर मंगलवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसान अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, किसान प्रदर्शन करते हुए इमारत की पहली मंजिल पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल पर कूद गए। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर राज्य मंत्री दादाजी भुसे मंत्रालय भवन के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों से बात कर रहे हैं। कुछ किसानों को हिरासत में लेकर मरीन

ड्राइव पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति खतरनाक मंत्रालय में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा- ह्वागर सरकार ने मंत्रालय में सुरक्षात्मक जाल पर कूदने से पहले किसानों की आवाज सुनी होती, तो आज ऐसी बात नहीं होती। सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। उन्होंने आगे कहा- मंत्रालय में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, लेकिन किसानों को हो रही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति खतरनाक है।

प्लास्टिक से सड़क बनाने के वादे को भूली मनपा

अब जब्त प्लास्टिक का ऑक्शन कर टेबल, बेंच, कुर्सी बनाने की तैयारी

मुंबई : सड़कों पर गट्टे भरने के लिए मनपा प्रशासन हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती है। इसके बावजूद हर साल सड़कों पर हजारों गट्टे बने रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मनपा ने मुंबई की सड़कों को प्लास्टिक के कचरे से बनाने की योजना बनाई थी। मनपा ने वर्ष 2019 में सर्कुलर निकाल कर कहा था कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मुंबई में सड़क बनाने पर किया जाएगा। लेकिन पिछले 4 साल में यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर एक साल के भीतर 5000 किलो से अधिक प्लास्टिक जब्त किया गया है।

मनपा ने सर्कुलर निकाल कर कहा था कि जब्त प्लास्टिक का इस्तेमाल अस्पल्ट की बनी सड़कों में किया जाएगा। मनपा अब जब्त प्लास्टिक



का का ऑक्शन करने की योजना बना रही है।

साथ ही प्लास्टिक का दोबारा प्रोसेस करके बेंच, पेंसिल बैंक, पेन आदि बनाए जाएंगे। मुंबई में वर्ष 2005 में आई भीषण बाढ़ का कारण प्लास्टिक का इस्तेमाल भी माना गया था। क्योंकि नागरिकों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक की वजह से गटर, नालियां, नाले भर गए थे जिससे पानी निकासी नहीं हो सकी और भारी बारिश की वजह से मुंबई में बाढ़ आ गई थी। तब



नगरसेवकों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की थी कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोका जाए और प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जाना चाहिए। इससे प्लास्टिक के प्रोसेस की भी समस्या खत्म हो जाएगी। मनपा ने वर्ष 2019 में जब्त व कचरे में फेंके गए प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़क बनाने पर करने का निर्णय लिया। इसके लिए बाकायदा सर्कुलर निकला गया। लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। वर्ष 2020 में तत्कालीन

मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी ने भी कहा था कि प्लास्टिक की पाबंदी के बाद मनपा द्वारा दुकानों और बाजारों में कार्रवाई के बाद जमा हुए प्लास्टिक का उपयोग मुंबई में मजबूत और टिकाऊ सड़क निर्माण के लिए करेगी। परदेशी ने जनवरी 2020 में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे तय करें कि मुंबई में बनने वाली सड़कों के रोड मटीरियल में 5 से 10 प्रतिशत प्लास्टिक का उपयोग किया जाए। सड़कों का टेंडर निकालते समय यह शर्त अनिवार्य किया जाए। सड़क निर्माण के लिए मनपा प्रत्येक विभाग में प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर शुरू किया जाए। सड़कों के मटीरियल में कैरीबैग, स्नेक्स पैकेट, दूध की थैली, डिजिट और कॉस्मेटिक, बोटल-थैलियों आदि वस्तुओं का उपयोग किया जाए।

मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को बड़ा झटका

कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

मुंबई : मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने मंगलवार को शहर की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को कोविड-19 के शिकार हुए लोगों के शवों के लिए बैग खरीदने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले में गिरफ्तारी के डर से शिवसेना (यूबीटी) की नेता पेडनेकर ने इस महीने की शुरूआत में अदालत के सामने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। एडिशनल सेशन जज एसबी जोशी ने मंगलवार को मामले में पेडनेकर और दो अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। दरअसल मामला कोविड -19 केंद्रों के 'घोटेले' से जुड़ा है। इसमें कथित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन में धन की हेराफेरी



और महामारी के दौरान बीएमसी की ओर से कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों के शवों के लिए बैग और मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं का

आरोप है। यह मामला पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। पेडनेकर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक महापौर रही थीं।

» मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को कोर्ट से बड़ा झटका
» कोविड में शवों के बैग खरीदने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामला
» कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

कुर्ला में पुराने विवाद में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, 7 गिरफ्तार

मुंबई : पुलिस ने मंगलवार को कहा कि मुंबई के कुर्ला पूर्व में दो परिवारों के बीच विवाद को लेकर साजिद अली शब्बीर कुरेशी नाम के एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में तीन महिलाओं सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चूनाभट्टी पुलिस के मुताबिक, शनिवार रात साजिद और उनके परिवार पर एक दर्जन से ज्यादा लोगों के समूह ने हमला किया था। साजिद को बचाने की कोशिश में साजिद के भाई को भी गंभीर चोटें आईं। घटना की शुरूआत मामूली झड़प से हुई जो बढ़ते-बढ़ते मारपीट तक पहुंच

गई। घटना के बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ धारा 302, 307, 323, 324, 326, 341, 120-बी, 143, 145, 147, 148 और 149 के तहत एफआईआर दर्ज की है और सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले पीड़ित और हमलावर लंबे समय तक छोटी-छोटी बातों पर झगड़ों में उलझे रहते थे और एक-दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज कराते थे।



संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

महंगाई का निकालना होगा स्थायी हल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर से दोहराया कि महंगाई पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता है। यदि आर्थिक गतिविधियों को गतिशील बनाना है तो महंगाई को थामना जरूरी है। जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी महंगाई की दर 4.8 प्रतिशत थी, जबकि जुलाई में तेजी से बढ़कर 7.44 प्रतिशत हो गई। टमाटर, प्याज, मटर, लहसुन और अदरक

जैसी सब्जियों की कीमतें पिछले कुछ महीनों में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। सब्जियों में 37 प्रतिशत, मसालों में 22 प्रतिशत, अनाज में 13 प्रतिशत, दूध में 8.3 प्रतिशत के साथ अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले तीन महीनों में थोक बाजार में टमाटर की कीमत 1,400 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई थी। हालांकि जुलाई 2023 में धातुओं, रसायन और रासायनिक उत्पादों, कपड़ा आदि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण कोर मुद्रास्फीति घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित उत्पादों में से खाद्य पदार्थों एवं पेट्रोलियम उत्पादों को हटाकर जो मुद्रास्फीति निकाली जाती है, उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई में उछाल खाद्य उत्पादों में होने वाली कीमत वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है।

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाली गिरावट की दर बहुत कम होने के कारण यह आशंका जताई जा रही है कि अगस्त में भी महंगाई की दर छह प्रतिशत से अधिक रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ का मानना है कि अस्थिर अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं ऊर्जा कीमतें, लंबे समय से जारी भू-राजनीतिक तनाव और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के बीच महंगाई को नियंत्रित करना किसी चुनौती से कम नहीं है।

आरबीआइ ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति के अंतर्गत वर्तमान के रेपो रेट 6.5 प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अगली मौद्रिक नीति में इसमें कितना परिवर्तन होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि महंगाई के कारण मांग पर कितना असर पड़ता है। मूल्य अनिश्चितता के कारण भविष्य के लिए निवेश और बचत पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। बढ़ती महंगाई का प्रभाव वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, कम आय वालों, दैनिक आय अर्जित करने वालों पर अधिक होता है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, जिससे आय असमानता भी बढ़ती है।

महंगाई को केवल प्रकृति की मार कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। नवीन भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ते कदमों के लिए मुद्रास्फीति हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव भी औसत भारतीय उपभोक्ता के जीवनयापन की लागत पर खासा प्रभाव डालता है। कुछ खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियां, अनाज और डेरी उत्पाद जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होने के कारण बाजार की शक्तियां अधिक लाभ उठाने के लिए कृत्रिम दबाव बनाना शुरू कर देती हैं। बाजार के असंतुलन का लाभ लेने में सट्टेबाज हमेशा ही सफल रहते हैं, जिसके कारण कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी चीनी तो कभी सोना, चांदी आदि की कीमतें बढ़ने लगती हैं। महंगाई का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो, इससे पहले ही तत्काल प्रभाव से इस समस्या से निपटने की आवश्यकता है। हालांकि आगामी माह में त्योहारी सीजन को देखते हुए एवं आने वाले समय में कुछ राज्यों एवं 2024 के आम चुनावों के कारण सरकार कीमतों को कम करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर भी रही है।

+91 99877 75650

editor@rookthoklekhani.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

इंडिया की बैठक से भाजपा चले जाओ का नारा की होगी शुरुआत - नाना पटोले

इंडिया में प्रधानमंत्री पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार

मुंबई : भाजपा की अत्याचारी सरकार के खिलाफ देशभर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिल कर 'इंडिया' आघाड़ी गठबंधन नाम से जोरदार शंखनाद किया है। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को दो दिनों के लिए मुंबई में आयोजित की गई है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि इंडिया की होने वाली बैठक के पहले 31 अगस्त को इंडिया आघाड़ी के लोगो (चिन्ह) का अनावरण किया जाएगा। केंद्र और राज्य की सत्तधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए पटोले ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मुंबई से ब्रिटिश सत्ता को 'देश छोड़ने का' का नारा दिया था, उसी तर्ज पर 'इंडिया' की मुंबई बैठक में



केंद्र की मोदी सरकार से भी 'चले जाओ' का नारा दिया जाएगा। नाना पटोले ने कहा कि मुंबई में होने वाली 'इंडिया' आघाड़ी की बैठक काफी अहम है। इस आघाड़ी में एनडीए में शामिल कुछ दल भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत 6 मुख्यमंत्री, विभिन्न दलों के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। पटोले ने कहा कि 'इंडिया' आघाड़ी के

पास प्रधानमंत्री पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन खुद बीजेपी के पास इस पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी से तंग आ चुके हैं, उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला गठबंधन करेगा लेकिन एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर हमारा मानना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक सवाल का जवाब देते हुए नाना पटोले ने कहा कि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने खुद साफ तौर

से कहा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के कुछ साथियों ने विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि ईडी के डर की वजह से बीजेपी सरकार के हाथ मिलाया है। शरद पवार ने पूछा है कि बीजेपी से हाथ मिलाने से पहले ये लोग महाविकास आघाड़ी की सत्ता में शामिल थे। फिर बताएं कि उन्होंने विकास के लिए काम क्यों नहीं किया। पटोले ने कहा कि मुंबई-गोवा हाईवे का काम करीब 17 साल से चल रहा है लेकिन ये सड़क पूरी नहीं हो पाई है। यह सड़क भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सड़क के ठेके में भाजपा के लोग भागीदार हैं। कमीशन के विवाद के कारण यह सड़क पूरी नहीं हो पाई है। कई ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए और इस वजह से कोंकण के लोगों को परेशानी हो रही है।

पंद्रह दिन में अग्निशमन व्यवस्था करे ठीक नहीं तो बिजली-पानी काट दिया जाएगा



मुंबई : मुंबई सांताक्रूज पूर्व स्थित गैलेक्सी होटल में आग लगने की घटना को मनपा के अग्निशमन विभाग ने गंभीरता से लिया है। होटल में अग्निशमन व्यवस्था चालू नहीं होने के कारण होटल मालिक को नोटिस जारी किया है। फायर ब्रिगेड प्रमुख रवींद्र अंबुलगेकर ने बताया कि नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि पंद्रह दिनों के भीतर होटल में अग्निशमन प्रणाली स्थापित करें अन्यथा बिजली और पानी काट दिया जाएगा। रविवार को सांताक्रूज पूर्व प्रभात कॉलोनी

स्थित चार मंजिला गैलेक्सी होटल में आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। तीनों मृतक अहमदाबाद से नैरोबी जाने के लिए मुंबई आए थे। फ्लाइट में देरी के कारण एयरलाइंस ने उन्हें इस होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी। शुरुआती जांच में अनुमान लगाया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जिसकी जांच चल रही है। सोमवार को दोबारा फायर ब्रिगेड द्वारा होटल का निरीक्षण किया गया जिसमें यह बात सामने आई कि होटल का

कोई भी फायर फाइटिंग सिस्टम चालू नहीं है। फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने कहा कि संबंधित होटल को नोटिस जारी किया गया है। चूंकि इसका निर्माण 1966 में हुआ था, इसलिए इसमें अग्निशमन प्रणाली का होना अनिवार्य नहीं था। लेकिन इसके बावजूद फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद होटल में फायर सिस्टम नहीं लगाया गया है जिससे बिना कारण तीन लोगों की मौत हो गई। फायर सिस्टम लगाने की अनदेखी के चलते होटल मालिक को नोटिस जारी किया गया है। आग से होटल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, पर्दे, कालीन, चादर, कंबल, कपड़े, और लकड़ी के फर्नीचर जल गए।

स्वास्थ्य विभाग में 10 हजार 949 पदों पर भर्ती



मुंबई : पर्चा फूटने और विभिन्न घोटालों की वजह से पिछले तीन साल से रुकी जन स्वास्थ्य विभाग की भर्ती प्रक्रिया अब फिर से शुरू हो जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के जरिए 10 हजार 949 पद भरे जाएंगे। यह पूरी भर्ती प्रक्रिया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के माध्यम से लागू की जाएगी। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान वर्ष 2021 में दौरान स्वास्थ्य विभाग में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक घोटाला हुआ था। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। अब मंत्री तानाजी सावंत की पहल पर एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में मेगा भर्ती शुरू होगी।

डायबटीज होने के बाद भी बार-बार मिठाई खाती थी पत्नी, 10 बार अपनी पत्नी को चाकू से गोदा



कांदिवली : एक महिला को डायबटीज थी। वो फिर भी मीठा खाना कम नहीं कर रही थी। उसका पति उसे कई बार टोकता था। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होते थे। एक वक्त ऐसा आया कि दोनों में झगड़े बढ़ने लगे और एक दिन गुस्से में आकर महिला के पति ने उस पर चाकू से 10 से ज्यादा वार किए। यहां कांदिवली इलाके में एक बुजुर्ग दंपती रहते थे। 79 साल के विष्णुकांत बालुर की पत्नी शकुंतला बालुर (76) काफी दिन से बीमार थी। दोनों को डायबटीज थी। पत्नी डायबटीज होने के बावजूद मिठाई खाने से बाज नहीं आ रही थी। विष्णुकांत उसे ऐसा करने से मना करता था। इस बात को लेकर दोनों का अक्सर झगड़ा होता रहता था।

बताया जा रहा है कि इस बात से गुस्साए विष्णुकांत ने बीते शुक्रवार को अपनी पत्नी की चाकू मार कर हत्या कर दी। इसके बाद खुदकुशी की कोशिश की घटना के थोड़ी देर के बाद जब बालुर की नौकरानी घर पहुंची तो उसने शकुंतला को निढाल हालत में बेड पर पड़े देखा। विष्णुकांत भी वहीं एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके शरीर से भी खून बह रहा था। नौकरानी ने तुरंत इसकी सूचना पड़ोसियों को दी। बाद में मौके पर समता नगर पुलिस पहुंची। पुलिस दंपति को अस्पताल ले गई। जांच में पता चला कि विष्णुकांत ने सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच शकुंतला के सिर और कान के पीछे नौ से 10 बार चाकू से वार किया। इसके बाद उसने खुद की गर्दन काट ली।

मलाड/ प्रस्ताविक सार्वजनिक सड़क बनकर तयार...

मुंबई: बीएमसी द्वारा भीड़भाड़ वाले मलाड स्टेशन आसपास की दुकानों के कुछ हिस्सों को गिराए जाने के चार महीने बाद, जिसमें प्रसिद्ध एमएम मिठाईवाला स्टोर के कुछ हिस्से भी शामिल थे, प्रस्तावित सार्वजनिक सड़क अब बनकर तैयार हो गई है और सार्वजनिक उपयोग के लिए तैयार है। आधिकारिक तौर पर आनंद रोड के रूप में जाना जाता है, इस खंड की कुल लंबाई 650 मीटर और चौड़ाई 13.40 मीटर है। जब बीएमसी ने इस साल अप्रैल में विध्वंस का काम किया था, तो कुछ दुकानों ने राहत के लिए शहर की सिविल अदालतों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं दी गई, जिससे बीएमसी को अपनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति मिल गई। बीएमसी के पी नॉर्थ वार्ड के अधिकारियों ने कहा कि सड़क अब तक एक तरफा थी



और अतिरिक्त सड़क की चौड़ाई के निर्माण के कारण अब पहली बार इसे दो तरफा किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, "हम इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ परामर्श कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि मानसून के कारण काम में देरी हुई, अन्यथा यह बहुत पहले ही तैयार हो गया होता।

मलाड स्टेशन क्षेत्र खरीदारों के लिए प्रमुख केंद्र है, जहां कृत्रिम आभूषणों की दुकानें, मछली बाजार और अन्य विशेष बाजार प्रतिदिन संचालित होते हैं। स्थानीय लोग भी नई सड़क का इंतजार

कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व मलाड पार्षद विनोद मिश्रा ने कहा कि यह इलाका पहले भी ट्रैफिक जाम के लिए जाना जाता रहा है, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी होती थीं। "चौड़ीकरण से न केवल मोटर चालकों को बल्कि पैदल चलने वालों को भी बड़ी राहत मिलनी चाहिए, जिन्हें जाम के बीच से अपना रास्ता बनाना होगा। हालांकि हमें प्रभावित पक्षों के पुनर्वास में भिन्नता के बारे में शिकायतें मिली हैं। इसे उचित तरीके से करने की आवश्यकता है बिना किसी को अतिरिक्त लाभ पहुंचाए," मिश्रा ने कहा। उन्होंने आगे बताया कि बीएमसी अक्सर प्रभावित दुकान मालिकों के लिए मुआवजे के उपाय के रूप में 'कुरार पैटर्न' का पालन करती है। इस पैटर्न के तहत, प्रभावित दुकान मालिकों को ग्राउंड-प्लस-वन मंजिला संरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी जाती है।

कारतूस के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार



मुंबई: सहार पुलिस ने रविवार को जिम्बाब्वे की एक 20 वर्षीय महिला को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद अपने सामान में एक जिंदा कारतूस ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया है। वह छत्र वीजा पर भारत की यात्रा कर रही थी और उसे लुधियाना में एक चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल होना था। पुलिस को घटना की जानकारी रविवार दोपहर एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों से मिली। जिम्बाब्वे के नडांगा की रहने वाली महिला को रविवार सुबह करीब 7 बजे मुंबई से नई दिल्ली के लिए हवाई जहाज में बैठना था। सुबह करीब पांच बजे उसके चेक-इन बैगेज की जांच के दौरान अधिकारियों को एक संदिग्ध वस्तु मिली। जांच करने पर अधिकारियों को बैग में एक जिंदा कारतूस मिला।

फडणवीस के खिलाफ अभद्र भाषा में आलोचना बर्दाश्त नहीं

भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर की उद्धव ठाकरे को चेतावनी

मुंबई : मुख्यमंत्री पद जाने से निराशाजनक हुए उद्धव ठाकरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ स्तरहीन टिप्पणी करना बंद करें वरना भाजपा के कार्यकर्ता इसका करारा जवाब देंगे। इस प्रकार की दो टूक चेतावनी भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने दी। सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सुनील कर्जतकर, मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये, मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन और प्रवक्ता ओमप्रकाश चौहान भी उपस्थित थे। दरेकर ने कहा कि, हिंगोली की सभा में उद्धव ठाकरे ने अत्यंत अभद्र भाषा में उपमुख्यमंत्री फडणवीस



के खिलाफ टिप्पणी की। उपमुख्यमंत्री फडणवीस राज्य में निवेश आमंत्रित करने के लिए जापान दौरे पर गये थे। जबकि उद्धव आराम करने के लिए विदेश गये थे। कोरोना महामारी के दौरान भ्रष्टाचार कर कलंकित हुए उद्धव ठाकरे को निष्फलक देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ टिप्पणी करने का हक नहीं है। सत्ता हाथ से जाने से तिलमिलाए भ्रमित हुए उद्धव ठाकरे बेबुनियाद

आरोप कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को राज्य और देश के विकास से कुछ भी लेना-देना नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए वे सिर्फ अपने घर के विकास में व्यस्त थे। केंद्र की जनकल्याणकारी किसी भी योजना की जानकारी उद्धव ठाकरे को नहीं है, इसके बावजूद वे 'विचार न करते हुए कुछ भी बकवास करना' वाली कहावत की तरह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते

हैं। शिवसेना के लिए अपना घर जलाकर राख करने वाले शिवसैनिकों को उद्धव ठाकरे ने क्या किया यह सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए।

दरेकर ने किसी के खिलाफ झूठ का सहारा न लेते हुए और बिना आलोचना करते हुए सिर्फ विकास के मुद्दे पर एक घंटे लगातार बोलकर दिखाने की ठाकरे को चुनौती दी है। दरेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब महाराष्ट्र के कई उद्योग अन्य राज्यों में गये। शिंदे-फडणवीस-पवार की सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आने की वजह से विदेशी निवेश के मामले में राज्य फिर से अक्वल स्थान पर पहुंच गया है।

भिवंडी में आगजनी का दौर जारी, प्लास्टिक मनी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग



मुस्तकीम खान भिवंडी : भिवंडी शहर और भिवंडी ग्रामीण में आग लगने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है हर दिन कहीं न कहीं आग लगने की घटनाएं हो रही हैं इसी कड़ी में तालुका की काम्बे ग्राम में स्थित एक प्लास्टिक मनी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। जिसमें लाखों का समान जलकर खाक हो गया। काम्बे ग्राम पंचायत के तलवाली नाका मिठपाड़ा इलाके में स्थित प्लास्टिक मनी बनाने वाली इस कंपनी में मंगलवार की सुबह अचानक धुआं निकलने के बाद आग लगने की जानकारी हुई। फैक्ट्री

में बड़ी मात्रा में कच्चा माल जमा होने के कारण आग ने भीषण रूप ले लिया जिसके कारण फैक्ट्री की छत का पत्रा टूट गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे और महज एक घंटे में आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। इस बीच, आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है। आग लगने का पता नहीं चल सका फैक्ट्री में जहां आग लगी थी उस तरफ का शटर बंद होने के कारण फैक्ट्री के कर्मचारी दूसरी तरफ से निकल कर अपनी जान बचाकर भागे। जिसके कारण इस आगजनी में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है।

नई मुंबई में आई फ्लू के मरीजों की संख्या डेढ़ हजार के करीब



नई मुंबई : नई मुंबई महानगरपालिका के रिकॉर्ड के अनुसार, नई मुंबई शहर में अब तक आई फ्लू के मरीजों की संख्या डेढ़ हजार के करीब पहुंच गई है। यह आंकड़ा २८ जुलाई से अब तक का है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। गंभीर बात यह है कि आई फ्लू के मरीजों का इलाज करने वाले कई डॉक्टर भी इसकी चपेट में हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, नई मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में हर रोज आई फ्लू के मरीजों का आंकड़ा शतक के करीब पहुंच रहा है। यह आंकड़े सिर्फ महानगरपालिका स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज करवा रहे मरीजों के हैं,

निजी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज करा रहे मरीजों की तादाद मिलाकर यह आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। महानगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं कि इस बीमारी को पैछलने से रोकने के लिए मनपा कर्मचारी घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। नई मुंबई महानगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत जवादे के अनुसार, आई फ्लू कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इसका इलाज आसानी से हो जाता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग संक्रमित हैं वे अपना इलाज सही तरीके से कराएं, खुद इलाज न करें और इसे पैछलने से बचाएं।

हाईकोर्ट का रेलवे प्रशासन से सवाल यात्रियों पर लापरवाही का टिकरा कैसे फोड़ सकते हैं?

मुंबई : उपनगरीय लोकल में यात्रियों की जानलेवा भीड़ पर सोमवार को मुंबई हाईकोर्ट ने भारी चिंता व्यक्त की। खचाखच भरी लोकल से यात्री नीचे गिरते हैं। भीड़ के कारण यात्री मजबूरन फुटबोर्ड पर खड़े रहते हैं। उनमें से कुछ लोगों की नाहक बलि चली जाती है। ऐसे समय में आप यात्रियों पर ही लापरवाही का टिकरा कैसे फोड़ सकते हैं? जनरल डिब्बों में पैर रखने की जगह नहीं होती है, उस समय उन यात्रियों को प्रथम श्रेणी या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति देंगे क्या? ऐसे सवालों की झड़ी कोर्ट ने रेलवे पर लगाई। उस पर रेलवे ने लोकल की भीड़ पर उपाय निकाले जाने को लेकर असमर्थता जताई। १३ साल पहले विरार लोकल से यात्रा कर रहे छात्र अल्पेश धोत्रे की लोकल



से गिरकर मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसके माता-पिता ने मुआवजे के लिए रेलवे दावा न्यायाधिकरण में अपील की थी। वहां उनका मुआवजा दावा खारिज कर दिया गया। इसलिए अल्पेश के माता-पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

एड. दीपक आजगेकर द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण के समक्ष सुनवाई हुई। इस समय काउंसिल बालासाहेब देशमुख द्वारा २० वर्षीय अल्पेश की विरार लोकल से गिरकर मौत होने का

दावा किया गया, उन्होंने तर्क दिया कि अल्पेश के माता-पिता रेलवे मुआवजे के हकदार हैं। अल्पेश की मौत के संबंध में रेलवे के मंडल प्रबंधकों की रिपोर्ट आरपीएफ और जीआरपी द्वारा की गई जांच से असंगत है।

ट्रिब्यूनल को मुआवजे के दावे के संबंध में सभी दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करना होगा। अल्पेश ने फुटबोर्ड पर खड़े होकर लापरवाही बरती है, यह रेलवे का दावा साबित करने वाला एक भी सबूत नहीं, ऐसा देशमुख ने कहा। इस पर आपत्ति

जताते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से एड. चिंतन अग्रवाल ने बहस की। उन्होंने कहा कि अल्पेश लोकल का वैध यात्री नहीं था। उसके पास कोई लोकल टिकट नहीं था। ऐसे में मुआवजे के लिए उसके माता-पिता के दावे को खारिज करने का रेलवे दावा न्यायाधिकरण का फैसला सही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अल्पेश के माता-पिता की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी दौरान न्यायाधीश चव्हाण ने उपनगरीय लोकल ट्रेनों में हर दिन होनेवाली भीड़ को लेकर चिंता जताई और रेलवे प्रशासन पर सवालों की बौछार कर दी। ऐसे में सबकी नजर अल्पेश की मौत से जुड़े मुआवजे के दावे पर कोर्ट के पैठसले पर टिकी है।

मुंबई में बिहार की साढ़े 12 वर्षीय बालिका के साथ कई बार दुष्कर्म... गर्भवती होने के बाद हुआ खुलासा



मुंबई : मुंबई में बिहार की साढ़े 12 वर्षीय बालिका के साथ कई बार दुष्कर्म करने के आरोपित 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा गर्भवती होने पर पीड़िता के स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचने पर हुआ। हालांकि आरोपित पीड़िता का पति निकला। आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब दोनों परिवारों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। चारकोप पुलिस ने बताया कि जांच में चौकाने वाला तथ्या सामने आया कि आरोपित पीड़िता

का पति है। पूछताछ में गिरफ्तार दुष्कर्म आरोपित ने पुलिस को बताया कि इस साल की शुरुआत में बिहार में दोनों के परिवारों की सहमति से उनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद वे दोनों मुंबई आ गए। 19 जून 2023 से वे चारकोप थाना अंतर्गत किराये के मकान में रह रहे हैं।

चिकित्सकों को बालिका के नाबालिग होने का संदेह
आरोपित ने बताया कि पेट में दर्द होने पर उन्हें पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी हुई और वह उसे लेकर शताब्दी

अस्पताल पहुंचा था। यहां जांच के दौरान चिकित्सकों को बालिका के नाबालिग होने का संदेह हुआ। पूछताछ में सामने आया कि उसकी उम्र महज 12 साल सात माह और 23 दिन थी। इसके बाद चिकित्सकों ने पुलिस को सूचित किया।

पाक्सो के तहत दर्ज होगा केस
पुलिस ने बताया कि आरोपित व पीड़िता के परिवारों के खिलाफ आईपीसी, पाक्सो अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं आरोपित के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं समेत पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। आरोपित को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सामान्य बीमारियों के इलाज पर दोगुना खर्च...!

मुंबई : अस्पतालों में भर्ती होने की आवश्यकता वाली सामान्य बीमारियों के इलाज की लागत पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है। यह अचंभित करने वाली जानकारी बीमा दावों के आंकड़ों से सामने आई है। इसके अलावा संक्रामक रोगों और श्वसन संबंधी विकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा दावे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि संक्रामक रोगों के लिए पहले मेडिकलेम ३० हजार तक होता था, लेकिन अब वह बढ़कर ८० हजार तक पहुंच गया है।

संक्रामक रोगों के लिए औसत स्वास्थ्य बीमा दावा २०१८ में २४,५६९ रुपए था, जो २०२२ में ६४,१३५ रुपए तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी १६० फीसदी से भी ज्यादा है। यह 'पॉलिसी बाजार' के आंकड़ों से साफ हो रहा है। मुंबई जैसे शहरों में तो ये रकम इससे भी ज्यादा है। यहां संक्रामक रोगों का औसत दावा ३०,००० रुपए से बढ़कर ८०,००० रुपए हो

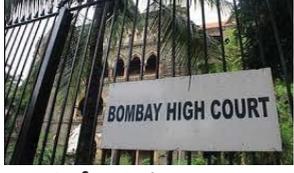


गया है। श्वसन संबंधी विकारों के लिए औसत दावा ४८,४५२ रुपए से बढ़कर ९४,२४५ रुपए हो गया है। हालांकि, मुंबई में यही दावा ८०,००० से १,७०,००० तक पहुंच गया है। पॉलिसी बाजार के मुख्य व्यवसाय अधिकारी अमित छाबड़ा का कहना है कि कोरोना के बाद उपभोक्ता वस्तुओं की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले यह आंकड़ा कुल बिल का तीन से चार फीसदी था। लेकिन अब यह १५ प्रतिशत तक पहुंच गया है। उपचार की बढ़ती लागत के कारण हर पांच साल में स्वास्थ्य बीमा कवरेज अपर्याप्त होता जा रहा है। मेडिकल खर्चों में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद कॉरपोरेट

कंपनियां सिर्फ तीन लाख तक का ही बीमा कवरेज देती हैं। ऐसे समय में जो लोग कॉर्पोरेट बीमा कवर पर निर्भर हैं, उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।

नई दवाओं, इलाज के तरीकों और इंटरनेट के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण उपचार महंगे होने लगे हैं। इसके कारण चिकित्सा महंगाई में सामान्य दर से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग और उपयोग बढ़ जाता है। इसके चलते चिकित्सा खर्च भी बढ़ जाता है। नागरिकों को अक्सर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से गुजरने के लिए प्रेरित किया जाता है।

मुंबई विश्वविद्यालय के चुनाव निलंबन के फैसले पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल



मुंबई : मुंबई विश्वविद्यालय (एमयू) ने 17 अगस्त को चुनावों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी थी, वहीं अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें एमयू के फैसले को चुनौती दी गई है और बताया गया है चुनावों के निलंबन का फैसला राजनीतिक दबाव के कारण लिया गया। याचिका का उल्लेख मंगलवार को न्यायमूर्ति सुनील शुक्ले और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ के समक्ष किया गया। अधिवक्ता सागर देवरे द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि सीनेट चुनावों पर रोक लगाने वाले एमयू द्वारा जारी परिपत्र को रद्द किया जाए और विश्वविद्यालय को दस सितंबर को निर्धारित चुनाव कार्यक्रम शुरू करने और पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाए। पीठ इस पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गई है।

इंडिया' की मुंबई बैठक में केंद्र की मोदी सरकार 'चले जाओ' का नारा



मुंबई : भाजपा की अत्याचारी सरकार के खिलाफ देशभर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिलकर 'इंडिया' गठबंधन नाम से जोरदार शंखनाद किया है। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक ३१ अगस्त और १ सितंबर को दो दिनों के लिए मुंबई में होगी। ३१ अगस्त को इंडिया गठबंधन के 'लोगों' का अनावरण किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मुंबई से ब्रिटिश सत्ता को 'देश छोड़ने का' नारा दिया था, उसी तर्ज पर 'इंडिया' की मुंबई बैठक में केंद्र की मोदी सरकार से भी 'चले जाओ' का नारा दिया जाएगा। कल सोमवार को गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को

संबोधित करते हुए नाना पटोले ने कहा कि मुंबई में होनेवाली 'इंडिया' गठबंधन की बैठक काफी अहम है। इस गठबंधन में एनडीए में शामिल कुछ दल भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत ६ मुख्यमंत्री, विभिन्न दलों के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। पटोले ने कहा कि 'इंडिया' गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन खुद भाजपा के पास इस पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी से तंग आ चुके हैं, उनकी लोकप्रियता तेजी से घट रही है। इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री पद

का उम्मीदवार कौन होगा? इसका पैठसला गठबंधन करेगा।

पटोले ने कहा कि मुंबई-गोवा हाईवे का काम करीब १७ साल से चल रहा है, लेकिन ये सड़क पूरी नहीं हो पाई है। यह सड़क भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सड़क के ठेके में भाजपा के लोग भागीदार हैं। कमीशन के विवाद के कारण यह सड़क पूरी नहीं हो पाई है। कई ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए और इस वजह से कोकण के लोगों को परेशानी हो रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मुंबई-गोवा राजमार्ग के काम की जांच कराई जानी चाहिए, तभी 'दूध का दूध और पानी का पानी' होगा।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 'सरकार आपके द्वार' अभियान पर जनता का पैसा लुटाया जा रहा है। यह सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है और उसका श्रेय ले रही है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि जब भी यह कार्यक्रम होता है तो वहां के लोग सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर करते हैं।

बाप्पा की राह में 93 खतरनाक पुल सूचीबद्ध, विभाग द्वारा चेतावनी पुलों के ऊपर से जाते समय भक्त सावधानी बरतें

मुंबई : बाप्पा के आगमन में महज चंद दिन ही रह गए हैं। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों ने अभी से ही विशाल मूर्तियों को पंडालों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। बाप्पा की मूर्ति ले जाते समय भारी भीड़ उमड़ रही है और गाजे-बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि, मनपा ने बाप्पा की राह में १३ खतरनाक पुल सूचीबद्ध किए हैं, जिसकी घोषणा भी कर दी गई है। इसलिए पुल विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि इन पुलों के ऊपर से जाते समय भक्त सावधानी बरतें। साथ ही यहां वे बहुत अधिक समय तक न ठहरें।

अंधेरी में ३ जुलाई २०१८ को गोखले ब्रिज ढहने से दो, जबकि १४ मार्च २०१९ को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 'हिमालय' ब्रिज ढहने से सात लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए मनपा ने मुंबई के सभी पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया है। साथ ही जरूरत के मुताबिक, मरम्मत करने के साथ ही नागरिकों की मांग के अनुसार, कुछ पुलों को ध्वस्त कर वहां नए



पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

मुंबई में करीब ३४४ पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करके छोटी-बड़ी मरम्मत, जबकि खतरनाक पुलों को गिराकर नए पुलों के निर्माण की योजना बनाई गई है। हालांकि, कुछ पुराने पुलों का अभी भी उपयोग किया जा रहा है। इसलिए मनपा ने गणेशोत्सव के दौरान इन पुलों का उपयोग करते समय सावधान रहने के लिए खतरनाक पुलों की सूची की घोषणा की है। करी रोड स्टेशन पर पुल, साने गुरुजी मार्ग पर (आर्थर रोड) के निकट चिंचपोकली पुल और भायखला परिसर के रेलवे मार्ग पर 'मांडलिक ब्रिज' पर एक बार में १६ टन से अधिक वजन न रखें। इस तरह की अपील मनपा के पुल विभाग ने की है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध राज्य के २९ अस्पतालों में चिकित्सा उपचार और सेवाएं मुफ्त!



मुंबई : राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के आधिपत्य वाले अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से मुफ्त हो गया है। इसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध राज्य के २९ अस्पतालों में चिकित्सा उपचार और सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाएंगी। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, बस कैबिनेट की मंजूरी में देरी है।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के

अधीन आनेवाले सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों की फीस, जांच और विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए न्यूनतम दरें ली जाती थीं। इसके अलावा कम वार्षिक आय वाले मरीजों को अलग-अलग छूट दी जाती थी। हालांकि, इस बीच राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के आधिपत्य वाले अस्पतालों में १५ अगस्त से इलाज पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। इसे लेकर हाल ही में शासनादेश जारी कर

दिया गया है। इस योजना से प्रदेश के सभी नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। फिलहाल, यह निर्णय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों पर लागू नहीं है। यहां जटिल सर्जरी, विभिन्न जांचों की जाती हैं।

उनमें से कुछ मरीजों का ही मुफ्त में इलाज किया जाता है, जबकि अधिकांश मरीजों से मध्यम शुल्क वसूल कर उपचार किया जाता है, जबकि कुछ मरीजों को कुछ उपचारों और परीक्षाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, इस बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हर नागरिक को अच्छा इलाज मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

मुंबई के आर्थिक कायापलट का बनेगा मास्टर प्लान...

नीति आयोग के सीईओ के साथ मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री की बैठक

मुंबई : राज्य सरकार और नीति आयोग मिलकर मुंबई के आर्थिक कायापलट का मास्टर प्लान तैयार करेंगे। मंगलवार को मंत्रालय में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बारे में प्राथमिक प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर दिसंबर तक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित उपस्थित थे। इस बैठक में मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के साथ आर्थिक विकास करने और इस क्षेत्र की जीडीपी 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई।



मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बारे में नीति आयोग से संपूर्ण समन्वय रखेगी। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की स्वतंत्र टीम नियुक्ति की जाएगी। देश में मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम और वाराणसी जैसे चार शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कुछ सुझाव दिए। सुब्रमण्यम ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि मुंबई सहित देश में

एमएमआर की मौजूदा जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 140 बिलियन डॉलर है। यह जीडीपी पुर्तगाल, कोलंबिया, सऊदी अरब, मलेशिया, इजरायल, चिली से भी ज्यादा है। एमएमआर की जनसंख्या वर्ष 2023 तक 2 करोड़ 70 तक बढ़ेगी पिछले 5 साल में मुंबई महानगर की विकास दर 5 से साढ़े पांच फीसदी रही है। 2030 तक मुंबई की जीडीपी बढ़ाने के लिए और 150 बिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत है।



नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड

● इवेंट के 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने जीता सोना

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में रविवार देर रात इतिहास रच दिया है। टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने 88.17 मीटर के अपने बेस्ट एफर्ट के साथ गोल्ड जीता। यह चैम्पियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में 19 अगस्त से 27 अगस्त तक खेली गई।



25 साल के नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पिछले साल यूजीन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, जिसे उन्होंने इस बार गोल्ड में बदला। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर जीता। उन्होंने 87.82 मीटर का बेस्ट एफर्ट निकाला। यह चैम्पियनशिप

1983 से हो रही है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में यह भारत का ओवरऑल तीसरा मेडल है। नीरज की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। कहा, प्रतिभाशाली नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाया है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून, उन्हें न सिर्फ एथलेटिक्स में चैम्पियन बनाता है, बल्कि पूरे खेल जगत में उन्हें उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है।

पीएम मोदी ने 51 हजार युवाओं को जॉइनिंग लेटर सौंपे 10 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी मिली

बोले-

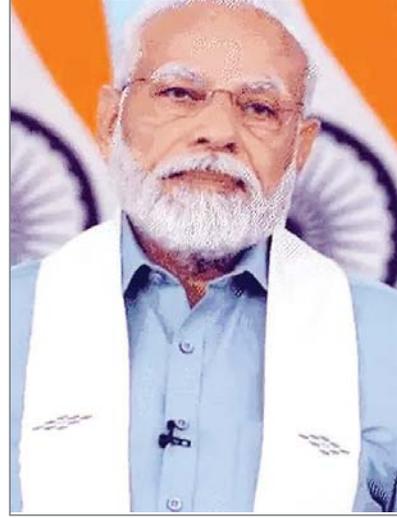
● भारत जल्द टॉप-3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम मोदी 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में वचुंअली शामिल हुए। उन्होंने अब तक करीब 5 लाख युवाओं को जॉइनिंग लेटर दिए हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 28 अगस्त को 8वें राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत 51 हजार 106 युवाओं को जॉइनिंग लेटर सौंपे। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया।

उन्होंने जॉइनिंग लेटर मिलने पर सबको बधाई दी और कहा कि भारत बहुत जल्द टॉप-3 अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। पीएम मोदी ने कहा, देश के हर युवा का सपना है कि वो देश का प्रहरी बने। आप देश की सेवा के साथ-साथ यहां के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। इसलिए आप सभी आजादी के अमृत काल के अमृत रक्षक हैं।

पीएम ने कहा, 'आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को कई गुना बढ़ा दिया है। भारत में बने फोन पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। मोबाइल के बाद भारत अब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर फोकस करेगा।'



करने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ दिल्ली पुलिस में भर्ती होती है। पीएम ने कहा- आने वाले सालों में फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर और विकसित होने वाले हैं।

भारत सरकार मेड इन इंडिया लैपटॉप-टैबलेट खरीदेगी- प्रधानमंत्री ने कहा, वो दिन दूर नहीं है, जब मोबाइल की तरह भारत में बने एक से बढ़कर एक लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे। वोक्ल फॉर लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लैपटॉप, टैबलेट खरीदने पर जोर दे रही है।

टूरिज्म सेक्टर में 13 से 14 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार- पीएम मोदी ने कहा कि देश में फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक टूरिज्म सेक्टर से भारत की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है। इससे युवाओं के लिए 13-14 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

गृह मंत्रालय के अलग-अलग विभागों में होती है भर्ती- रोजगार मेले में जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम

10 महीने में 5 लाख लोगों को जॉइनिंग लेटर मिले

22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। तब पीएम ने कहा था- हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। पीएम ने पिछले 10 महीनों में 8 रोजगार मेलों में करीब 5 लाख युवाओं को जॉइनिंग लेटर दिए हैं।

जनधन योजना से वित्तीय समावेशन में क्रांति आई, मंत्री बोलीं- 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में अब तक खोले गए 50 करोड़ जनधन खातों में दो लाख करोड़ रुपये जमा हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जन खातों को बड़ी उपलब्धि बताया है। वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा कि जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल परिवर्तन ने देश में वित्तीय समावेशन के मामले में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 50 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में जोड़ा गया।

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की नौवीं वर्षगांठ पर सीतारमण ने कहा कि 55.5 प्रतिशत बैंक खाते महिलाओं की ओर से खोले गए हैं और 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से



एक है। योजना के तहत बैंक खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से 3.4 गुना बढ़कर 16 अगस्त 2023 तक 50.09 करोड़ हो गई। कुल जमा राशि भी मार्च 2015 तक 15,670 करोड़ रुपये से बढ़कर अगस्त 2023 तक 2.03 लाख

करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएमजेडीवाई के जरिए लाए गए बदलावों और डिजिटल परिवर्तन से नौ वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में क्रांति आई है। हितधारकों, बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के सहयोगात्मक प्रयासों से पीएमजेडीवाई देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई...। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि जनधन-आधार-

मोबाइल (जेएएम) ने आम आदमी के खातों में सरकारी लाभों के सफल हस्तांतरण को सक्षम बनाया है। कराड ने कहा, पीएमजेडीवाई खाते प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी जन-केंद्रित पहल का आधार बन गए हैं। इसने समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित वर्ग के समावेशी विकास में योगदान दिया है। वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। यह देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रहा है।

पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कई लाभ प्रदान करता है। इसमें खाते में न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके

अलावा मुफ्त रूपे डेबिट कार्ड, दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी सेवाएं इसमें शामिल हैं।

शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में खुले। हालांकि बाजार में शुरुआती कारोबार में बिकवाली दिखी पर फिर बाजार संभल गया। सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर सेंसेक्स 105.33 (0.16 प्रतिशत) अंक चढ़कर 64,991.84 जबकि निफ्टी 44.50 (0.23 प्रतिशत) अंक मजबूत होकर 19,310.30 के लेवल पर कारोबार करता दिख रहा है।

दोबारा खुलेंगे टैक्स से जुड़े पुराने मामले, आयकर विभाग की बड़ी तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी। आयकर विभाग कुछ पुराने और बड़े मामलों को री-ओपन करने की तैयारी में है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बीते 23 अगस्त को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि केवल उन मामलों को री-ओपन और री-असेसमेंट नहीं किया जाएगा जहां अपीलीय अधिकारियों का निर्णय अंतिम हो गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील दीपक जोशी ने बताया कि सीबीडीटी के ताजा निर्देश की अच्छी बात यह है कि कम से कम उन मामलों को नहीं टच किया जाएगा, जिससे जुड़े अपील, अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित नहीं है और कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल महीने के फैसले से पहले फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। दीपक जोशी के मुताबिक कुछ टैक्सपेयर्स के लिए यह संभवतः मुकदमेबाजी का एक और दौर है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल महीने में प्रधान आयकर



आयुक्त बनाम अभिसार बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड मामले की सुनवाई करते हुए माना था कि आईटी अधिकारी किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में, आयकर अधिनियम की धारा 153-ए के तहत री-असेसमेंट कार्यवाही के दौरान टैक्सपेयर्स की आय में कोई वृद्धि नहीं कर सकते हैं। धारा 153ए उस व्यक्ति की कमाई तय करने की प्रक्रिया बताती है, जिसके खिलाफ तलाशी ली गई है। इसका मकसद अघोषित आय को टैक्स के दायरे में लाना है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि धारा 147/148 के तहत शर्तें पूरी होने की स्थिति में री-असेसमेंट किया जा सकता है। बता दें कि आयकर विभाग के पास धारा 147 के तहत किसी व्यक्ति के पहले से जमा किए गए आयकर रिटर्न की समीक्षा करने का अधिकार है। धारा 148 के तहत किसी भी कर योग्य आय का आकलन किया जा सकता है, जिसका मूल्यांकन अधिनियम के सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया गया है।

रेल कंपनी के शेयर ने पकड़ी बुलेट ट्रेन की रफ्तार, 2 साल में इनवेस्टर हुए मालामाल

नई दिल्ली, एजेंसी। रेलवे स्टॉक टेक्ससमैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयरों ने सोमवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। टेक्ससमैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर 12 पैसे से ज्यादा की तेजी के साथ 149.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 131.05 रुपये पर बंद हुए थे। टेक्ससमैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 40.49 रुपये है।

2 साल में शेयरों में 390 प्रतिशत की तेजी

टेक्ससमैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में पिछले 2 साल में 390 पैसे का उछाल आया है। कंपनी के शेयर 27 अगस्त 2021 को बीएसई में 29.87 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 अगस्त 2023 को बीएसई में 149.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। अगर किसी इनवेस्टर ने 2 साल पहले कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो मौजूदा समय में इन शेयरों की वैल्यू 5 लाख रुपये होती।



6 महीने में 235 प्रतिशत चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

टेक्ससमैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयर पिछले 6 महीने में 235 पैसे चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 28 फरवरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 44.20 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 अगस्त 2023 को बीएसई में 149.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 1 महीने में टेक्ससमैको रेल एंड इंजीनियरिंग के शेयरों में 43 पैसे का उछाल आया है। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 24 पैसे चढ़ गए हैं।

एल्युमीनियम रेल वैगन्स के लिए हिंडालको से डील

टेक्ससमैको रेल एंड इंजीनियरिंग और हिंडालको इंडस्ट्रीज ने वर्ल्ड क्लास एल्युमीनियम रेल वैगन्स और कोच डिजेल और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पिछले दिनों एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। इससे इंडियन रेलवे को अपने एमिशन गोल्लस को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस पार्टनरशिप के तहत भारत में एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का प्लान है।

विवादों के साये में अडानी समूह का प्रोजेक्ट, आसान नहीं आगे की राह

नई दिल्ली, एजेंसी। गौतम अडानी समूह ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी की तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी उठाई है लेकिन यह सबकुछ इतना आसान नहीं है। अडानी समूह के सामने इस प्रोजेक्ट की कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती सेकलिंग



टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की ओर से मिल रही है। **कानूनी चुनौती** दरअसल, बहरीन के शाही परिवार द्वारा समर्थित सेकलिंग टेक्नोलॉजीज ने भी धारावी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई थी लेकिन इसको पछड़कर अडानी समूह ने जीत हासिल की। अब प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने इस बोली प्रक्रिया को कानूनी चुनौती है। आरोप है कि अडानी समूह को प्रोजेक्ट देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2018 के मूल टेंडर को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया। इसके लिए सेकलिंग ने सबसे अधिक बोली लगाई थी। इसके बाद 2022 में नई शर्तों के साथ प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया ताकि अडानी समूह को जीत मिल सके। इस मामले की सुनवाई मुंबई की अदालत में हो रही है। आगामी 31 अगस्त को एक बार फिर सुनवाई होगी। हालांकि, अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार ने सेकलिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

विपक्ष को मिला हथियार लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में यह विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। चुनाव से पहले यह

महाराष्ट्र के साथ देशभर में बड़ा मुद्दा बन सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी के समर्थन की सरकार है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में हजारों स्थानीय परिवार से जुड़े लोगों ने अडानी समूह को लेकर अविश्वास की बात कही है। इसके मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी की आगामी नियामक जांच ने धारावी में कुछ लोगों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया है। धारावी पुनर्विकास समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कोर्डे ने कहा कि हिंडनबर्ग घटना के बाद लोगों को अडानी की छवि के बारे में संदेह है। धारावी में कुछ वर्ग में अडानी समूह के प्रोजेक्ट का विरोध भी हो रहा है। अगस्त की शुरुआत में लगभग 300 विपक्षी समर्थक और निवासी अडानी की भागीदारी पर आपत्ति जताने के लिए धारावी में एकत्र हुए थे।

बीते साल नवंबर में समूह की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने 5,069 करोड़ रुपये की निवेश की पेशकश कर स्लम कॉलोनी के रिडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। यह स्लम कॉलोनी 259 हेक्टेयर में फैली है। सेंट्रल मुंबई के बांदा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के समीप इस परियोजना में 20 हजार करोड़ रुपये के पुनर्विकास की संभावना है। प्रोजेक्ट के तहत जो धारावी में 1 जनवरी 2000 से पहले से रह रहे हैं उन्हें मुफ्त में पक्का मकान दिए जाने का प्रस्ताव है। वहीं, साल 2000 के बाद बसे लोगों को इसके लिए कीमत चुकानी होगी।

सोने से अधिक तेजी से बढ़ रही चांदी की कीमतें

नई दिल्ली, एजेंसी। बीते हफ्ते सराफा बाजारों में सोना जहां 249 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, वहीं चांदी के भाव 3248 रुपये प्रति किलोग्राम उछल गए। चांदी की इस बढ़ती कीमतों के पीछे एक वजह 5जी टेक्नोलॉजी भी है। आईबीजेए द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सराफा बाजारों में 18 अगस्त को सोना 58471 रुपये पर था, जबकि चांदी 70447 रुपये पर बंद हुई थी। शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 58720 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बंद हुआ और चांदी 73695 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। इससे पहले गुरुवार को सोना 58734 और चांदी 73667 रुपये पर बंद हुई थी।

पिछले एक हफ्ते में सोने की अपेक्षा चांदी के दाम बहुत अधिक उछले। यह 13 गुनी अधिक रफ्तार से भागी। एक हफ्ते पहले चांदी के रेट 70447 रुपये प्रति किलो थे, लेकिन केवल 5 कारोबारी दिनों में 73695 रुपये पर पहुंच गई।



कुल 3248 रुपये प्रति किलोग्राम की उछाल दर्ज की गई। जबकि, इन पांच दिनों में सोना केवल 249 रुपये प्रति 10 ग्राम ही महंगा हुआ।

क्यों बढ़ रहे चांदी के भाव

केडिया कर्मांडिटज के प्रसीडेंट अजय केडिया ने बताया कि सोने की तुलना में चांदी का बेहतर प्रदर्शन, जो

सोने-चांदी के अनुपात 79.31 से संकेत मिलता है, 78 को तोड़ने पर तेज हो सकता है। मजबूत अमेरिकी डेटा और कठोर फेड टिप्पणियों द्वारा समर्थित अमेरिकी डॉलर की ताकत कम हो सकती है। चांदी को 72500 पर समर्थन, 76300 पर प्रतिरोध मिला। शॉर्ट कवरीज के कारण ओपन इंटरस्ट में 49.81 प्रतिशत की गिरावट आई।

बीएसई और एनएसई ने दिग्गज कंपनियों पर लगाया लाखों का जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसी। शेयर बाजारों ने सूचीबद्धता नियमों को पूरा करने में विफल रहने पर सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम और गैस कंपनियों... इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन और गेल सहित आधा दर्जन से अधिक कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने स्वतंत्र और महिला निदेशकों की जरूरी संख्या से संबंधित सूचीबद्धता नियमों को अनुपालन नहीं किया है। अलग-अलग दि सूचना में कंपनियों ने बीएसई और एनएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण दिया गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती।

ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, आईओसी को 5.36 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने को

कहा गया है। गैस कंपनी गेल पर 2.71 लाख रुपये, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 3.59 लाख रुपये, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 3.6 लाख रुपये, ऑयल इंडिया लिमिटेड पर 5.37 लाख रुपये और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड पर 5.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आईओसी पर बोर्ड में आवश्यक एक महिला निदेशक नहीं होने के कारण जुर्माना लगाया गया है। इसे छोड़कर सभी कंपनियों पर स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या रखने के मानदंड का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। आईओसी ने कहा कि निदेशकों (स्वतंत्र और महिला निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है।

रिलीज हो रही बॉलीवुड की यह फिल्में, 'जवान' से लेकर 'द ग्रेट इंडियन फैमिली' तक मचाएंगी धूम

शाहरुख खान की मोस्ट अपेक्टेड फिल्म 'जवान' 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन एटली ने किया है। वहीं इसमें लीड रोल में नयनतारा ने काम किया है।

द ग्रेट इंडियन फैमिली : विक्की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म 'द ग्रेट इंडियन फैमिली' 22 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म एक फैमिली ड्रामा पर बेस्ड है।

सुखी : शिल्पा शेठ्टी की फिल्म 'सुखी' 22 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म एक पंजाबी हाउसवाइफ सुखप्रीत की कहानी है, जो अपने दोस्तों के साथ 20 साल बाद रीयूनियन में के लिए दिल्ली जाती है। इसी के इर्द-गिर्द फिल्म की कहानी है।

द वैक्सीन वॉर : विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी 'द वैक्सीन वॉर' 28



सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि कोरोना महामारी के दौरान इंडियन साइंटिस्ट ने वैक्सीन को कैसे बनाया। इसमें नाना पाटेकर, अनुपम खेर, राइमा सेन जैसे कई एक्टर नजर आने वाली हैं।

गोल्डफिश : कल्कि केकलां, दीप्ति नवल, और रजत कपूर स्टारर फिल्म 'गोल्डफिश' में मां-बेटी के नाजुक रिश्ते को दिखाया जाएगा। यह फिल्म 1 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।

हैप्पी टीचर्स डे : राधिका मदान और निघ्रत कौर की ये फिल्म 5 सितंबर को टीचर्स डे पर ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की कहानी स्कूल, टीचर्स और स्टूडेंट्स के आस-पास घूमती है।

विवेक अग्निहोत्री ने छोड़ा बॉलीवुड, बोले- मूर्ख एक्टर्स के साथ काम नहीं कर सकता

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अक्सर अपनी सोच और विचारों के चलते सुर्खियां बटोरते हैं। अब विवेक अग्निहोत्री ने बॉलीवुड एक्टर्स को मूर्ख बताते हुए कहा है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता और बॉलीवुड से इस्तीफा दे रहा हूँ। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि वो कमर्शियल फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। इसकी वजह बॉलीवुड के अशिक्षित एक्टर्स हैं जिनका दुनिया के बारे में कोई सोच या दृष्टिकोण ही नहीं है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में विवेक ने खुलासा किया कि उन्होंने कमर्शियल सिनेमा छोड़ दिया, क्योंकि जिन एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है वो दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 'मैं यह अहंकार में कह रहा हूँ, बल्कि मैं सच कह रहा हूँ। मुझे लगने लगा था कि जिन

सितारों के साथ मैं काम करता हूँ, वे पढ़े-लिखे नहीं हैं और उन्हें दुनिया के बारे में कोई समझ नहीं है। मैं उनसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हूँ



और मेरा वैश्विक दृष्टिकोण उनसे कहीं ज्यादा है।

विवेक ने कहा कि बॉलीवुड एक्टर्स की वजह से आज हमारा

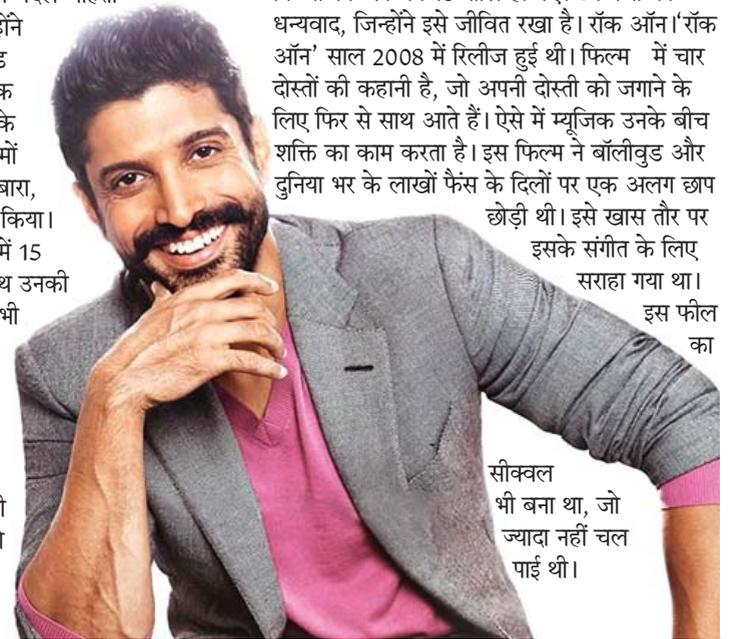
सिनेमा एकदम डंब हो गया है। भारतीय सिनेमा इतना मूर्ख क्यों है? इसकी वजह हमारे एक्टर्स हैं। ये एक्टर्स डायरेक्टर और राइटर्स को भी मूर्ख बना देते हैं। कमर्शियल सिनेमा से इस्तीफा देने के पीछे की वजह बताते हुए विवेक ने कहा, 'फिल्म कभी भी मेरी वजह से नहीं जानी जाती, फिल्म हमेशा मूर्ख अभिनेता की वजह से जानी जाती है। इसलिए मैंने मानसिक रूप से बॉलीवुड से इस्तीफा दे दिया है' बॉलीवुड में कमर्शियल फिल्मों से शुरूआत करने वाले विवेक अग्निहोत्री ने चॉकलेट, धन धना धन गोल और हेट स्टोरी जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से विवेक अग्निहोत्री ने समाज को आईना दिखाने वाली बेहतरीन फिल्मों की हैं जिसमें 'द ताशकंद फाइल्स' और 'द कश्मीर फाइल्स' जैसी शानदार फिल्मों शामिल हैं।

फरहान अख्तर ने बॉलीवुड में पूरे किये 15 साल

फरहान अख्तर ने बतौर अभिनेता बॉलीवुड में अपने 15 साल पूरे कर लिए हैं। अब वो अपनी डेब्यू फिल्म रॉक ऑन का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़ा एक पोस्ट किया है। इस फिल्म ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। दर्शक इसके गानों पर झूमते नजर आते हैं। इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया था। फरहान ने डायरेक्टर के तौर पर अपनी शुरूआत साल 2001 में आई फिल्म 'दिल चाहता है' से की थी, लेकिन उन्होंने एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में आइकोनिक फिल्म 'रॉक ऑन' से डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाग मिला भाग में काम किया। बतौर अभिनेता बॉलीवुड में 15 साल पूरे होने के साथ-साथ उनकी डेब्यू फिल्म रॉक ऑन ने भी अपने 15 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। यह फिल्म निर्देशक अभिषेक कपूर के लिए भी काफी महत्व रखती है, वो इसे अपने दिल के सबसे करीब फिल्म बताते हैं।

फरहान अख्तर और अभिषेक कपूर अपनी इस फिल्म के 15 साल पूरे होने पर जश्न मना रहे हैं। इस फिल्म में फरहान ने बैंड मैजिक के मुख्य सिंगर के रूप में अभिनय किया था।

फिल्म में उनके साथ अर्जुन रामपाल, पूरब कोहली और ल्यूक केनी दिखाई दिए थे। रॉक ऑन की रिलीज के 15 साल पूरे होने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैजिक को बने 15 साल हो गए। उन फैंस का धन्यवाद, जिन्होंने इसे जीवित रखा है। रॉक ऑन 'रॉक ऑन' साल 2008 में रिलीज हुई थी। फिल्म में चार दोस्तों की कहानी है, जो अपनी दोस्ती को जगाने के लिए फिर से साथ आते हैं। ऐसे में म्यूजिक उनके बीच शक्ति का काम करता है। इस फिल्म ने बॉलीवुड और दुनिया भर के लाखों फैंस के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी थी। इसे खास तौर पर इसके संगीत के लिए सराहा गया था।



सिक्वल भी बना था, जो ज्यादा नहीं चल पाई थी।